



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016/9 वैशाख 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अप्रैल, 2016

संख्या: टी0सी0पी0-(बी)2-3/2014 (रुलज)पीओ.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी.सी.पी-(ए)3-1/95 (पार्ट)-I तारीख 2.5.2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र/ई गजट,, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध “क” का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग— I, (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 के उपाबन्ध— “क” में,—

(1) स्तम्भ संख्या: 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“22 (बाईस) ”

(2) स्तम्भ संख्या: 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“अनिवार्य अर्हता(एं) :-

किसी विश्वविद्यालय या आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में बी. टैक की उपाधि।

या

किसी विश्वविद्यालय या आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्लानिंग स्नातक या प्लानिंग में टेक्नोलोजी स्नातक :

परन्तु उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो उपरोक्त शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् नगर एवं ग्राम योजना विधियों के अधीन गठित किसी प्राधिकरण में या नगर एवं ग्राम योजना विभाग में अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

(ख) **वांछनीय अर्हता:—**

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।”।

(3) स्तम्भ संख्या: 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) तीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकिंडमैंट आधार पर।

(ii) सत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकिंडमैंट आधार पर”।

(4) स्तम्भ संख्या: 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वरिष्ठ योजना प्रारूपकारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में मान्यता प्राप्त बी.टैक की उपाधि या आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त उपाधि सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को

सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर नीचे वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (ii) में से प्रोन्नति द्वारा।

-----18 प्रतिशत

(ii) वरिष्ठ योजना प्रारूपकारों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका आर्किटेक्चरल असिसटेंटशिप में मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय डिप्लोमे या ड्राफ्ट्समैनशिप के ट्रेड में दो वर्ष के मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (i) में से प्रोन्नति द्वारा।

-----17 प्रतिशत

(iii) कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में मान्यता प्राप्त बी.टैक की उपाधि या सिविल इंजीनियरिंग/प्लानिंग में मान्यता प्राप्त उपाधि सहित छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर नीचे वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (iv) में से प्रोन्नति द्वारा।

----- 5 प्रतिशत

(iv) कनिष्ठ अभियंताओं में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमे सहित नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त वर्णित सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग (iii) में से प्रोन्नति द्वारा।

----- 30 प्रतिशत

(v) उपरोक्त समस्त के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राप्त बी. टैक की उपाधि या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या प्लानिंग में बी.टैक की मान्यता प्राप्त उपाधि रखने वाले और इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से, सैकण्डमेंट आधार पर :

परन्तु योजना अधिकारी के पद को भरने के लिए निम्नलिखित 22 बिन्दु “पद” आधारित रोस्टर अपनाया जाएगा।

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, सातवां, बारहवां, और सत्रहवां	सम्भरक प्रवर्ग (पोषक) (i)
दूसरा, आठवां, तेरहवां, और अठारहवां	सम्भरक प्रवर्ग (पोषक) (ii)
तीसरा	सम्भरक प्रवर्ग (पोषक) (iii)
चौथा, नौवां, चौदहवां, उन्नीसवां, इक्कीसवां और बाइसवां	सम्भरक प्रवर्ग (पोषक) (iv)
पांचवां, छठा, दसवां, ग्यारहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, और बीसवां	सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणः—रोस्टर प्रत्येक बाइसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात्, रिक्ति उसी प्रवर्ग में से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।”।

(5) विद्यमान स्तम्भ संख्या: 15—क (I) (ग) का लोप किया जाएगा।

(6) स्तम्भ संख्या: 15—क (II) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“संविदात्मक उपलब्धियां

संविदा के आधार पर नियुक्त योजना अधिकारी को 15300/—रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ाव तारी की जाती है, तो पश्चात्पूर्ति वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/—रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(7) स्तम्भ संख्या: 15—क के निबंधन और शर्तें संख्या VII के खण्ड (क), (ग) और (घ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 15300/— की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए पश्चात्पूर्ति वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹459/—की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि कर हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। ;

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।; और

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।” ।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) ।

उपाबन्ध- “ख”

योजना अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, प्रशासनिक सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य प्रशासनिक सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना विभाग)हिमाचल प्रदेश सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने योजना अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार योजना अधिकारी के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15300/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-(B)2-3/2014 (Rules) PO dated 26.4.2016 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TOWN & COUNTRY PLANNING

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th April, 2016

No. TCP-(B)2-3/2014(Rules)PO.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Town & Country Planning, **Planning Officer, Class-I (Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules, 2013 notified vide this Department Notification of even number dated 2.5.2013 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Planning Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh, Town and Country Planning Department, Planning Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013,-

(1) For the existing provisions against Column No.2, the following shall be substituted, namely:-

“22 (Twenty Two)”

(2) For the existing provisions against Column No.7, the following shall be substituted, namely:-

“Essential Qualification(s):-

B.Tech Degree in Urban/City/Town /Regional Planning from a University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planners, India.

OR

Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning from a University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planners, India:

Provided that preference will be given to the candidates possessing at least 3 years experience in Urban/City/Town Regional Planning's work under any authority constituted under Town & Country Planning Laws or in the Town & Country Planning Department after acquiring the above qualification.

Desirable Qualification:-

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh”

(3) For the existing provisions against Column No.10 the following shall be substituted, namely:-

“(i) 30% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

(ii) 70% by promotion failing which on secondment basis”.

(4) For the existing provisions against Column No.11, the following shall be substituted, namely:-

“(i) By promotion from amongst the Senior Planning Draughtsman possessing a recognized B.Tech Degree in Urban /City /Town/ Regional Planning or Degree in Architecture or Civil Engineering with 03 (Three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (ii) mentioned below.18%

(ii) By promotion from amongst the Senior Planning Draughtsman possessing a recognized 03 (Three) years Diploma in Architectural Assistantship or two years Certificate Course in the trade of Draughtsmanship with 05 (Five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (i) mentioned above17%

(iii) By promotion from amongst the Junior Engineers (Civil) possessing a recognized B.Tech Degree in Urban /City/ Town/ Regional Planning or Degree in Civil Engineering /Planning with 06 (Six) years regular service or regular combined with

continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (iv) mentioned below5%

- (iv) By promotion from amongst the Junior Engineers possessing a recognized 03 (Three) years Diploma in Civil Engineering with 09 (Nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the feeder category (iii) mentioned above30%

(v) Failing all on secondment basis from amongst the incumbents of this post possessing a recognized B./Tech Degree in Urban/City/Town/Regional Planning or Degree in Architectural Engineering or Civil Engineering or B.Tech Degree in Planning and working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments:

Provided that for filling up the post of Planning Officer the following 22 points "Post" based roster shall be followed.

Roster Point No.	Category
1 st , 7 th , 12 th , & 17 th	Feeder category (i)
2 nd , 8 th , 13 th & 18 th	Feeder category (ii)
3 rd	Feeder category (iii)
4 th , 9 th , 14 th , 19 th , 21 st & 22 nd	Feeder category (iv)
5 th , 6 th , 10 th , 11 th , 15 th , 16 th & 20 th	Direct Recruitment through concerned recruiting agency

Note:—the roster will be repeated after every 22nd point till the representation to all categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from amongst the category which vacates the post”.

- (5) The existing provisions against Col.No.15-A (I)(C) shall be deleted.

(6) For the existing provision against Column No.15-A (II) the following shall be substituted, namely:-

“Contractual Emoluments

The Planning Officer appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount @ ₹15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ₹459/-(3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.”.

(7) For the existing provisions against clause (a),(c) and (d) of Terms and Conditions No.VII of Column 15-A, the following shall be substituted, namely:-

- (a) The contract appointed will be paid fixed contractual amount @ ₹ 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 459/-(3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given ;
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursment and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year ; and.

- (d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government”.

By order,
Manisha Nanda
Additional Chief Secretary (TCP).

Annexure-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Planning Officer and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary (Town & Country Planning)

This agreement is made on this..... day of in the year.....Between Sh/Smt.....s/o/d/o Shri.....R/o....., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Administrative Secretary (Town & Country Planning) to the Govt. of H.P. (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Planning Officer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Planning Officer on contract basis for a period of 1 year commencing on day of and ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 15300/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimated the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is

over. The Women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

2.

 (Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and Full Address)

2.

 (Name and Full Address)

(signature of the SECOND PARTY)

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 28th April, 2016*

No. SJE-A-A(3)-4/2014.—In pursuance to the power conferred under Section-18 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2015, No.4 of 2006, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Ashutosh Gupta, #2979/11, Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmour as Member of H.P. State Commission for Protection of Child Rights from the field of Juvenile Justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities, for a period of three years from the date on which he assumes office or till attaining the age of 60 years whichever is earlier.

By order,
Anuradha Thakur,
Secretary (SJ&E).

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA**Co. Petition No. 6 / 2016****IN THE MATTER OF:**

1. **Mr. Raman Puri** S/o Mr. Ganga Prasad Puri,
R/o C-42, Mansarovar Garden, New Delhi-08.
2. **Mr. Ganga Prasad Puri** S/o Mr. Mangal Dass Puri,
R/o C-42, Mansarovar Garden, New Delhi-08.
3. **Mr. Ajay Puri** S/o Mr. Ganga Prasad Puri,
4. R/o C-42, Mansarovar Garden, New Delhi-08.

.....*Petitioners*

Versus

Blue Coast Infrastructure Development Pvt. Ltd.,

7th, Shopping Complex, Sector-1,
Parwanoo, H.P.-173220.
Through its Director

Also at:

Blue Coast Infrastructure Development Pvt. Ltd.,
415-417, Antriksh Bhawan,
22, K.G. Marg, New Delhi-110001

.....*Respondents*

ADVERTISEMENT OF PETITION FOR WINDING UP

Notice is hereby given that a petition for winding up of the above named Company subject to the supervision of the Court was presented to the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla on **11th day of April, 2016** by the above named investors of the said Company. And that it has been directed the said petition shall be heard before the said Court on the **19th day of May, 2016** and any creditor or contributory of the said Company desirous to support or oppose the making of an order for the winding up of the said Company under the Act above, should appear at the time of hearing, by himself or his advocate, attorney, or agent for that purpose; and copy of the said petition will be furnished to any creditor or contributory of the said Company requiring the same, on application to the said Court on payment of the charges for the same.

PLACE: SHIMLA
DATED: 13/03/2016

Petitioners
Through Counsel:

(ANSHUL ATTRI) (ROHIT BHAROLL)
ADVOCATES

OFFICE: TKG LAW ASSOCIATES
A-130, Defence Colony,
New Delhi-110024.

Also at:

Arcvet, Below Isolation Hospital,
Bagh, Boileauganj, Shimla-5, H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th April, 2016

No.HHC/GAZ/ 14-368/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 13 days' paternity leave w.e.f. 15.2.2016 to 27.2.2016 with permission to prefix Sunday fell on 14.2.2016 in favour of Sh. Ashok Kumar, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, Barsar, District Hamirpur, H.P.

Certified that Sh. Ashok Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Ashok Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, Barsar, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001**NOTIFICATION***Shimla, the 25th April, 2016*

No.HHC/GAZ/ 14-342/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave for 28.9.2015 & 29.9.2015 and 03 days' commuted leave w.e.f. 29.3.2016 to 31.3.2016 in favour of Smt. Anita Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Mandi, H.P.

Certified that Smt. Anita Sharma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Anita Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001**NOTIFICATION***Shimla, the 20th April, 2016*

No.HHC/GAZ/ 14-272/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 19 days' commuted leave w.e.f. 20.12.2015 to 7.1.2016 in favour of Sh. Hoshier Singh Verma, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Nalagarh, H.P.

Certified that Sh. Hoshier Singh Verma is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Hoshier Singh Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Nalagarh, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2016

No. HHC/GAZ/14-223/97.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 04 days' commuted leave w.e.f. 17.2.2016 to 20.2.2016 with permission to suffix Sunday fell on 21.2.2016 in favour of Shri Pune Ram, Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla, H.P.

Certified that Shri Pune Ram has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pune Ram would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2016

No. HHC/GAZ/14-329/2012.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 06 days' commuted leave w.e.f. 15.2.2016 to 20.2.2016 in favour of Sh. Gaurav Kumar, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal, H.P.

Certified that Sh. Gaurav Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Gaurav Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 17/2016.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लाहड़, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि० मी० 95/0 से कि०मी० 140/0 (नयी आर०डी० 85/900 से 129/235) को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकबा (है०में)
हमीरपुर	हमीरपुर	लाहड़	630/1	00-00-59
			631	00-00-40
			632	00-00-76
			680/1	00-00-21
			681	00-00-32
			683	00-06-11
			684	00-06-22
			685/1	00-00-06
			686/1	00-00-09
			694/1	00-00-05

			695 / 1	00-01-20
			696 / 1	00-00-66
			697 / 1	00-00-50
			698 / 1	00-00-30
			699 / 1	00-00-24
			700 / 1	00-00-24
			701 / 1	00-00-36
			702 / 1	00-01-74
			747 / 1	00-01-07
			748 / 1	00-00-20
			749 / 1	00-00-40
			750 / 1	00-00-85
			751 / 1	00-00-99
			1178 / 1	00-04-30
			1179 / 1	00-01-62
			1187 / 1	00-03-22
			1195 / 1	00-00-22
			किता 27	0-32-92

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
अति० मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 19/2016.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डुग्धा खुर्द, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय

उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि० मी० 95/0 से कि०मी० 140/0 (नयी आर०डी० 85/900 से 129/235) को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकवा(है०में)
हमीरपुर	हमीरपुर	डुग्घा खुर्द	347	00-01-78
			347	00-01-78
			348 / 1	00-00-78
			354 / 1	00-00-39
			365 / 1	00-01-54
			365 / 3 / 1	00-01-74
			किता 5	0-06-23

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
अति० मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 2016

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5)22/2016.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पंजाहली, तहसील व जिला

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि० मी० 95/० से कि०मी० 140/० (नयी आर०डी० 85/900 से 129/235) को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकबा (हे० में)
हमीरपुर	हमीरपुर	पंजाहली	449 / 1	0-00-27
			450 / 1	0-00-28
			451 / 1	0-00-38
			453 / 1	0-01-64
			454 / 1	0-00-56
			455 / 1	0-00-90
			किता 6	0-04-03

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अति० मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अप्रैल, 2016

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 23/2016.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ककडयाणा, तहसील व

जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला —घागस —घुमारवी —हमीरपुर— नादौन— कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग—88 (नया 103) कि० मी० 95/० से कि०मी० 140/० (नयी आर०डी० 85/900 से 129/235) को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकवा (कनाल मरले में)
हमीरपुर	हमीरपुर	ककडयाणा	5 / 1	0-2
			6 / 1	0-2
			7 / 1	0-2
			12 / 1	0-1
			13 / 1	0-2
			14 / 1	0-1
			38 / 1	0-3
			704 / 189	0-2
			735 / 703 / 1	0-1
			735 / 703 / 2	0-4
			735 / 703 / 3	0-3
			736 / 703	कम अज मरला
			737 / 703	0-1
			738 / 703	कम अज मरला
			739 / 190	0-1
			740 / 190	0-1
			741 / 190	0-1
			191 / 1	0-1
			194 / 1	0-1
			648 / 195 / 1 / 1	0-1

			649 / 195 / 1	0-1
			200 / 1	0-1
			671 / 518 / 201 / 1	कम अज मरला
			673 / 518 / 201 / 1	0-2
			618 / 519 / 203 / 1	0-1
			578 / 520 / 1	0-1
			204 / 1	0-2
			580 / 205 / 1	0-1
			581 / 205	0-1
			207 / 1	0-2
			210 / 1	0-1
			210 / 1 / 1	0-1
			650 / 11	0-1
			651 / 211	0-1
			212 / 1	0-1
			214 / 1	0-1
			215 / 1	0-1
			653 / 216	0-1
			652 / 216 / 1	0-2
			218 / 1	0-1
			586 / 222 / 1	0-1
			250 / 1	0-4
			251 / 1	0-5
			252 / 1	0-4
			253 / 1	0-4
			254 / 1	0-7
			257 / 1	0-2
			258 / 1	0-2
			259 / 1	0-2
			260 / 1 / 1	0-1
			262 / 1	0-4
			274 / 1	0-5
			276	0-4
			282 / 1	0-11
			372 / 1	0-5
			374 / 1	0-2

			376/1	0-3
			378	0-3
			379	0-4
			किता 65	6-18

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अति० मुख्य सचिव (लोक निर्माण)

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 35/2016.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ठमाणी चम्याला, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि० मी० 95/0 से कि०मी० 140/0 (नयी आर०डी० 85/900 से 129/235) को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकवा (है० में)
हमीरपुर	बडसर	ठमाणी चम्याला	126/1	0-00-26
			238	0-00-53
			388/1	0-01-02

			391 / 1	0-00-32
			391 / 2	0-00-84
			392 / 1	0-01-34
			393	0-01-09
			395 / 1	0-01-70
			किता 8	0-07-10

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / -
अति० मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

In the Court of Collector, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 24 /13 of 2009

Date of Institution: 02-04-2009

State of Himachal Pradesh

Versus

Smt. Kamal Nand w/o Sh. Sachidanand

Notice:-Proceedings U/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972

To

Smt. Kamal Nand w/o Sh. Sachidanad, Resident of B-69, Shivalik, Malviya Nagar New Delhi-110017.

WHEREAS, a case for the violation of section 118 of HPT & LR Act, 1972 has been instituted against the respondent Smt. Kamal Nand w/o Sh. Sachidanad, r/o B—69, Shivalik Malviya Nagar New Delhi-110017, is respect of land comprised in Khata/Khatauni No. 36/46, Khasra No. 251/2/1 & Khasra No. 251/2/2/ measuring 0-10 bighas situated in Village Chabal Tehsil Kasauli, District Solan H.P. The Respondent Smt. Kamal Nand was served by e-mail through her Representative, Sh. Rajesh Tomar, on dated 29-02-2016 for appearing on 31-03-2016.

And whereas, on the said date the Representative of the Respondent requested telephonically to adjourn the case to 08-04-2016. But No one appeared on 08-04-2016.

NOW THEREFORE, this publication under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued to the Respondent/Representative mentioned above who is informed through this Notice that She should appear in this court on **07-05-2016 at 2:00 PM** personally or through counsel failing which the ex-parte proceeding shall be taken according to law.

Given, under my hand and the seal of this court on 20th day of April, 2016.

Sd/-
District Collector,
Solan, District Solan (H.P.).

In the Court of Collector, District Solan, Himachal Pradesh**Case No. 12 /13 of 2014***Date of Institution: 25-07-2014*

State of Himachal Pradesh

Versus

Smt. Neelam Aggarwal, w/o Sh. Chetan Aggarwal, and others.

Notice:-Proceedings U/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972

WHEREAS, a case for violation of Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy & Land Reform Act, 1972 has been instituted against Sh. Krishan Dutt Sharma, s/o Sh. Randheer Singh, who has sold the land comprised in Khata/Khatauni no.3/5 Khasra No. 11,14, 15, 16,Kita-4 measuring 98 bighas situated at Ajmergarh, Tehsil Kasauli, District Solan to Smt. Neelam Aggarwal who is a Non-Agriculturist. It has been reported that said Sh. Krishan Dutt Sharma, has died and you, the following are the, legal Representative (LRs) of Sh. Krishan Dutt Sharma.

1. Sh. Kushal Chand
2. Sh. Narinder Kumar
3. Smt. Kanta
4. Smt. Rani

(all residents of Village/Mauja Sihardi (Chakki Mod), Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

And whereas, the summons sent on available address have been received un-served with the report that you are not residing at the given address. Thus the service of summon could not be effected in ordinary manner.

NOW THEREFORE, this publication under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued to the LR's of Sh. Krishan Kumar mentioned above who are informed through this Notice that they should appear in this court on 13-05-2016 at 2:00 PM personally or through counsel failing which the ex-parte proceeding shall be taken according to law.

Given, under my hand and the seal of this court on 13th day of April, 2016.

Sd/-
District Collector,
Solan, District Solan (H.P.).

